PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Pioneer, Delhi
Fri, 18 Mar 2016, Page 5
Width: 21.25 cms, Height: 9.45 cms, a4r, Ref: pmin.2016-03-18.41.117

DPR on forestry intervention for Clean Ganga

PNS ▒ NEW DELHI

The Forest Research Institute (FRI) submitted to Water Resource & Ganga Rejuvenation Ministry, a Detailed Project Report (DPR) on forestry intervention for a Clean Ganga, emphasising on extensive plantations in natural, agricultural, and urban landscapes as also mass awareness drives to boost efforts for protecting the river. The DPR aims at achieving an increase in the flow of river water.

According to the Ministry, the experts used remote sensing and GIS technologies for spatial analysis and modeling of pre-delineated Ganga riverscape covering 83,946sq.Km out of a much larger Ganga River basin area in the country.

FRI has designed four sets of field data formats to obtain site specific information on proposed forestry plantations in natural, agricultural, and urban landscapes along the river course and in other conservation interventions.

More than 8,000 data sheets were obtained from five States along the river course. The institute also developed software to collate, analyse and report generation on potential plantation and treatment models.

Extensive plantations in natural, agricultural, and urban landscapes besides conservation interventions such as soil and water conservation, riparian wildlife management, wetland management and supporting activities such as policy and law interventions, concurrent research, monitoring andevaluation, and mass awareness campaigns have been envisioned in the DPR.

Altogether, 40 different plantation and treatment models have been selected for implementation by five States — Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal.

The project will be implemented over a period of five years by the State Forest Departments of these five states in Phase-I (2016-2021), the statement said.

As part of the project, active involvement of two battalions of Eco Task Force has been envisaged in Uttarakhand and Uttar Pradesh for raising plantations in difficult terrains.

The specific State forest departments are also expected to involve ITBP, Nehru Yuva Kendra Sangathan and civil society organisations for various proposed activities, including monitoring and awareness campaigns.

The DPR will be released by the Minister for Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Uma Bharti, on March 22, 2016. The meeting will also be attended by the Environment Minister Prakash Javadekar.

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Millennium Post, Delhi
Fri, 18 Mar 2016, Page 6
Width: 16.51 cms, Height: 8.19 cms, a4, Ref: pmin.2016-03-18.52.55

Clean Ganga: DPR on forestry intervention on Mar 22

MPOST BUREAU

NEW DELHI: The Detailed Project Report (DPR) on forestry intervention for a Clean Ganga, which envisages extensive plantations in natural, agricultural and urban landscapes as also mass awareness drives to boost efforts for protecting the river, will be released here next week.

Union Minister for Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Uma Bharti, will release the DPR on March 22. A day-long workshop has also been planned on the matter, which will be attended by Environment Minister Prakash Javadekar, an official statement said.

The government had entrusted Forest Research Institute (FRI), Dehradun, to prepare the DPR in April last year aiming to

achieve an increase in the river's water flow.

The FRI submitted the draft DPR to the National Mission for Clean Ganga (NMCG)on February 16 this year. The final report, prepared after incorporating suggestions and comments by NMCG and other officials, will now be released by Bharti.

FRI has designed four sets of field data formats to obtain site-based information on proposed forestry plantations in natural, agricultural, and urban landscapes along the river course and other conservation interventions.

More than 8,000 data sheets were obtained from five states along the river course. The institute also developed software to collate, analyse and report generation on potential plantation and treatment models. Extensive plantations in natural, agricultural, and urban landscapes besides conservation interventions such as soil and water conservation, riparian wildlife management, wetland management and supporting activities such as policy and law interventions, concurrent research, monitoring and evaluation, and mass awareness campaigns have been envisioned in the DPR.

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Navbharat Times, Delhi
Fri, 18 Mar 2016, Page 13
Width: 4.39 cms, Height: 6.84 cms, a4, Ref: pmin.2016-03-18.62.90

हरे-भरे होंगे गंगा के किनारे

प्रस, नई दिल्ली : सरकार गंगा के किनारों को हरा-भरा बनाने के लिए जल्द ही एक योजना लॉन्च करने जा रही है। इस कवायद का मकसद गंगा के किनारों को खूबसूरत बनाने के साथ ही पर्यावरण का संरक्षण करना भी है। इस सिलसिले में मंत्रालय ने एक डीपीआर तैयार कराई है। इसे जल संसाधन मंत्री उमा भारती 22 मार्च को लॉन्च करेंगी। इस मौके पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद रहेंगे। इस योजना के तहत पूरे देश में गंगा के किनारे पौधे लगाए जाएंगे। यह काम राज्यों को करना होगा।

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Rashtriya Sahara, Delhi
Fri, 18 Mar 2016, Page 13
Width: 4.80 cms, Height: 8.60 cms, a4, Ref: pmin.2016-03-18.49.182

स्वच्छ गंगा के लिए वनरोपण पर डीपीआर 22 को

नई दिल्ली (भाषा)। स्वच्छ गंगा के लिए नदी किनारे वानिकी हस्तक्षेप पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अगले सप्ताह यहां जारी की जाएगी, जिसमें प्राकृतिक, कृषि और शहरी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में वनरोपण का और नदी को बचाने के लिए प्रयास मजबूत करने के लिहाज से जन जागरुकता अभियान का भी विचार है। यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्री उमा भारती 22 मार्च को डीपीआर जारी करेंगी, जिस पर एक दिन की कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसमें पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी भाग लेंगे। सरकार ने नदी में जल का प्रवाह बढ़ाने के दृष्टिकोण के साथ वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून को पिछले साल अप्रैल में डीपीआर तैयार करने का काम सौंपा था।

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Haribhumi, Delhi
Fri, 18 Mar 2016, Page 11
Width: 15.78 cms, Height: 12.51 cms, a4, Ref: pmin.2016-03-18.66.142

नमामि गंगे मिशन के तहत सरकार का एक और प्रभावी कदम

गंगा के किनारों पर होगा वनरोपण

गंगा को साफ और स्वच्छ करने की दिशा में सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। नमामि गंगे मिशन के तहत गंगा के किनारों को सुरक्षित व मजबूत बनाने के लिए वनरोपण योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया।

हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली

इस योजना के लिए केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती अगले सप्ताह 22 मार्च को एक विस्तृत रिपोर्ट जारी करेंगी।

केंद्र सरकार के नमामि गंगे यानि गंगा संरक्षण कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के किनारे पेड़ लगाने की योजना है। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने इस वानिकी हस्तक्षेप योजना की एक विस्तृत रिपोर्ट वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) देहरादून से तैयार कराई है, जिसके मसौदे को जल संसाधन मंत्रालय को सौंप दिया गया है।

अगले सप्ताह उमा भारती जारी करेंगी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

परियोजना का लक्ष्य

मंत्रालय के अनुसार पांच राज्यों के लिए 40 अलग-अलग वृक्षारोपण और ट्रीटमेंट मॉडल्स का चयन किया गया है। यह परियोजना पांचों राज्यों के वन विभागों द्वारा पहले चरण में पांच साल 2021 तक पूरी करने का लक्ष्य तय किया गया है। इस परियोजना में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों में पेड़-पौधे उगाने के लिए इको टास्क फोर्स की दो बटालियनों की सक्रिय भागीदारी की परिकल्पना की गई है।

क्या है विशेषताएं

गंगा के किनारे वनरोपण परियोजना में वैज्ञानिक कार्यपद्धति को शामिल किया गया है, जिसमें देश के भीतर गंगा नदी थाले के बहुत विशाल क्षेत्र में से पूर्व-परिसीमित 83,946 वर्ग किलोमीटर गंगा क्षेत्र के आकाशीय विश्लेषण और मॉडलिंग के लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस जैसी तकनीकों का इस्तेमाल भी शामिल है। परियोजना की अंतिम रिपोर्ट में गंगा के किनारे की प्राकृतिक, कृषि और शहरी क्षेत्रों में प्रस्तावित वन रोपण और अन्य पारंपरिक संरक्षण विधियों पर जानकारी जुटाने के लिए फील्ड डाटा के प्रारूप के चार सेट तैयार किए हैं। संस्थान ने संभावित वृक्षारोपण और ट्रीटमेंट मॉडलों से संबंधित आंकड़ों के मिलान, विश्लेषण और रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक सॉफ्टवेयर भी विकसित किया है।